बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 26

निर्यात की चिंता

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश का व्यापार घाटा पिछले एक वर्ष की अवधि में सबसे निचले स्तर पर है।

देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर फरवरी 2019 में 9.6 अरब डॉलर हो गया। जबकि जनवरी 2019 में यह 14.7 अरब डॉलर था।

बहरहाल, इन आंकड़ों के बावजूद इसे इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारे बाह्य खाते में स्थिरता आ रही है। तथ्य यह है कि आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में देश की ढांचागत समस्या बरकरार है और वृहद आर्थिक स्थिरता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

खासतौर पर कमजोर निर्यात वृद्धि बताती है कि अगर मांग में सुधार होता है तो आयात के भुगतान का संघर्ष जारी रहेगा।

फरवरी 2019 में सालाना आधार पर निर्यात केवल 2.4 फीसदी बढ़ा। यह जनवरी में दर्ज 3.7 फीसदी के स्तर से कम है। अभियांत्रिकी और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि की दर धीमी रही। उदाहरण के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात में 2 फीसदी की कमी आई। यह स्पष्ट है कि इस वित्त वर्ष के पहले निर्यात वृद्धि को लेकर जो भी अनुमान लगाया गया था वह गलत साबित हुआ।

यह सही है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा कतिपय भारतीय वस्तुओं को किए जाने वाले निर्यात की प्राथमिकता को वापस लिए जाने के बाद निर्यात क्षेत्र के लिए वापसी करना और भी मुश्किल होगा। यह बात देश के अभियांत्रिकी निर्यात के लिए खासतौर पर सही है क्योंकि उसे शून्य टैरिफ वाले देशों से तगड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।

बीते कुछ वर्ष के दौरान अनुमतियों और कारोबारी सुगमता के मोर्चे पर कुछ सुधार देखने को मिला है लेकिन यह इतना नहीं है कि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर सके। ऐसे में अल्प या मध्यम अवधि में इन क्षेत्रों में निर्यात में अचानक तेज वृद्धि का अनुमान लगाना कतई सही नहीं होगा।

भारतीय निर्यातक महासंघ ने भी निर्यात क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के लिए वैश्विक हालात को उत्तरदायी ठहराया हे। परंतु यह दावा जांच परख में खरा नहीं उतरा। उदाहरण के लिए डायचे बैंक के मुताबिक साप्ताहिक हार्पेक्स शिपिंग इंडेक्स इसके विपरीत बातें बताता है। उसका कहना है कि जनवरी में वैश्विक व्यापार में सुधार आना शुरू हो गया।

व्यापार घाटे में कमी आने की वजह निर्यात क्षेत्र का सुधरा हुआ प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह आयात में गिरावट की वजह से हुआ है। इसके लिए तेल आयात के बिल में आई गिरावट को प्रमुख वजह माना जा सकता है। जैसा कि हमने अतीत में भी देखा है, बाह्य खाते को स्थिर बनाने के लिए ऐसी गिरावट को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। बल्कि हकीकत इसके उलट है। सोने के आयात में कमी आई है और इससे कई पर्यवेक्षक चकित हैं। परंतु गैर तेल- गैर स्वर्ण आयात में एक बार फिर गिरावट आई है। जनवरी में 0.8 फीसदी की गिरावट के बाद वह फरवरी में 3.7 फीसदी गिर गया। यह बहुत परेशान करने वाला रुझान है। देश में कमजोर औद्योगिक मांग इसका उदाहरण है।

आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर समग्र आंकड़ों से सामंजस्य बनाना भी आसान नहीं है। अगर देश का सकल घरेलू उत्पाद उच्चतम स्तर पर है तो यह समझना मुश्किल है कि आयात मांग में गिरावट क्यों आ रही है। वहीं रिकॉर्ड आर्थिक वृद्धि के दौर में निर्यात वृद्धि में कमजोरी को समझ पाना भी मुश्किल है। ये तमाम बातें उन चिंताओं को भी रेखांकित करती हैं जो हमारे समय के अर्थशास्त्री लगातार उठा रहे हैं।

बिनय सिन्हा

मोदी की विदेश नीति की पांच गलतियां

भारत पांच वर्ष पहले की तुलना में चीन से कमतर नजर आ रहा है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

कौन सी भावना अधिक तीव्र है, भय या प्रीति? इस सवाल का जवाब तो कोई मनोविज्ञानी ही दे सकता है। एक स्तंभकार तो केवल तथ्य जुटा सकता है, जांच परखकर उन्हें कल्पना और मिथ्या प्रचार से अलग कर सकता है और एक महत्त्वपूर्ण बहस को जन्म दे सकता है। ट्रोलिंग (किसी के पीछे पड़ना और परेशान करना) को हम प्रगति का सूचक मानते हैं।

पिछले दिनों चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव को रोककर भारत को बड़ा झटका दिया। चीन ने न केवल चौथी बार ऐसे प्रस्ताव को अवरुद्ध किया बल्कि चीन के सरकारी या पार्टी नियंत्रित मीडिया में आई टिप्पणियों में भारत को लेकर तमाम तरह की चेतावनी भी दी गईं। इनमें सबसे रूखी टिप्पणी वहां के सत्ताधारी दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में आई। पत्र ने भारतीय जनता पार्टी के क्रुद्ध कार्यकर्ताओं की तस्वीर के साथ नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह इन परिस्थितियों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं। अखबार ने लिखा कि चीन भारत का मित्र है, उसके राष्ट्रवाद का बंधक नहीं। चीन ने गत वर्ष वुहान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई वार्ता को लगभग पुनर्परिभाषित किया है, मानो वह कह रहा है कि अगर भारतीय चुनावों के वक्त उसके सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं आए हैं तो उसने अपना वादा निभाया है। बाकी मामलों में पुराना नियम लागू होगा।

चीन के इस दंभ के खिलाफ भारतीय प्रतिक्रिया की बात करें तो इस तरह की घेराबंदी के बाद भी भारत ने चीन का नाम तक लेने का साहस नहीं किया और उसने 'एक देश' को लेकर अपनी 'निराशा' जाहिर की। अमेरिका ने बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए चीन का नाम लिया और उसका वक्तव्य भारत की तुलना में कहीं अधिक कड़ा है।

मोदी सरकार की मजबूती में कोई कमी नहीं आई है लेकिन अब वह अपनी दबंगई का प्रयोग चुनिंदा ढंग से कर रही है। हालांकि इसमें भी विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आम चुनाव से दो महीने पहले मार्च 2019 में मोदी का भारत, शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे चीन का प्रतिकार करने में घबराया हुआ नजर आ रहा है, जबकि अपेक्षाकृत मित्रवत रहे अमेरिका के साथ एक स्वदेशी कारोबारी युद्ध छेड़ दिया गया है। जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें अपमानित करते हैं उनके समक्ष घुटने टेक देते हैं और हमारे लिए आवाज उठाते हैं, उनसे हम लड़ते भी हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं।

आइए बात करते हैं मोदी के विदेश नीति सिद्धांत की पांच गलतियों के बारे में:

1- हम यह समझ पाने में नाकाम रहे हैं कि रणनीतिक गठजोड़ करने के लिए बड़ा दिल होना आवश्यक है: अमेरिका हमारा प्रमुख रणनीतिक सहयोगी रहा है लेकिन ट्रंप समेत अमेरिका के शीर्ष प्रशासन में भारत को लेकर एक किस्म की ऊब पैदा हो चुकी है। ट्रंप को एक ढीठ बच्चा मानकर खारिज किया जा सकता है लेकिन क्या हमारी स्थिति ऐसा करने की है? आप इस बात पर हंस सकते हैं कि वह हार्ली डेविडसन बाइक पर भारतीय शुल्क को लेकर किस तरह चिंतित थे लेकिन वह भी हमारे स्वदेशी अर्थशास्त्र को अगंभीर करार दे सकते हैं। आयातित औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें घटाना एक अच्छा नैतिक और राजनीतिक कदम है। परंतु इसका क्रियान्वयन अचानक मूल्य नियंत्रण और आयात पर प्रतिबंध के साथ नहीं किया जाना चाहिए। भारत द्वारा एमेजॉन और वॉलमार्ट के खिलाफ जंग छेड़ने पर अमेरिका हैरत में होगा क्योंकि भारत खुद अपने ई-कॉमर्स और डिजिटल फाइनैंस क्षेत्र में चीनी निवेश का स्वागत कर रहा है।

पुलवामा की घटना के बाद अमेरिका ने जिस तरह भारत का साथ दिया वह उल्लेखनीय है क्योंकि मोदी और ट्रंप के आपसी रिश्तों और समझ में तनाव देखा गया है। नवंबर 2017 के बाद से दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है और नवंबर 2018 में ब्यूनस आयरस में जी-20 शिखर बैठक में ऐसी वार्ता का प्रयास नाकाम रहा। ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उनकी निजी नाराजगी दूर नहीं की गई तो वह तस्वीर खिंचवाने जैसी बातों में समय नहीं गंवाते। भारत अगर व्यापारिक मोर्चे पर थोड़ी रियायत दे तो इससे उसे नुकसान नहीं होगा।

ट्रंप अफगानिस्तान में सेना नहीं मांग रहे। वह रूस की एस-400 राइफल न खरीदने और ईरान में चाबहार बंदरगाह बंद करने को भी नहीं कह रहे। उनकी मांग केवल इतनी है कि कुछ शुल्क दरों में रियायत दी जाए। समझदार नेता अपनी लड़ाइयां सावधानी से चुनते हैं। खासतौर पर मित्रों के साथ अपनी लड़ाइयां।

2- बड़ी और अहंकारी ताकतों के एकतरफा तुष्टीकरण का गलत आकलन: भारत ने अमेरिका के साथ कारोबारी मोर्चे पर झगड़ा मोल लिया जबकि उसके साथ हमारा व्यापार अधिशेष 6,000 करोड़ डॉलर का है। जबकि चीन के साथ इतनी ही राशि का घाटा होने के बावजूद उसे अबाध पहुंच दी जा रही है। चीनी वस्तुओं और निवेश के लिए बाजार शायद इसलिए खोला गया ताकि भारत के प्रति उसका रुख नरम रहे।

ऐसा कुछ नहीं हुआ। दो वर्ष पहले चीन डोकलाम में घुसा। अब संदेश कुछ ऐसा है कि अगर चुनावी वक्त में हम डोकलाम या चुमर में नहीं घुस रहे तो हमारा शुक्रिया कहिए। वह भी एक चीनी फोन, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अमेरिका से हम छूट चाहते हैं जबकि चीन को रियायत दे रहे हैं।

3- व्यक्ति केंद्रित विदेश नीति से लगाव- मोदी का अपना कद और करिश्मा है। परंतु यह पेशेवर कूटनीति का स्थान नहीं ले सकता। हमें आंतरिक बहस और चर्चा के जरिये नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है।

हो सकता है सऊदी शहजादे को गले लगना पसंद आता हो और वह तुरत-फुरत निर्णय लेते हों लेकिन शी चिनफिंग इससे नाखुश हो सकते हैं या इसे चापलूसी समझ सकते हैं। इसके अलावा तंग श्याओफिंग के बाद ऐसे ताकतवर चीनी नेता होने के बावजूद हो सकता है उन्हें वह व्यक्तिगत शक्ति न हासिल हो जो मोहम्मद बिन सुलेमान को रियाद में या मोदी को नई दिल्ली में हासिल है। शी चिनफिंग एक संगठित और सक्षम तंत्र के साथ काम करते हैं जो मोदी की कैबिनेट से अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शी चिनफिंग के साथ मोदी ने जो लुभावना तरीका अपनाया, जो झियान, वुहान और अन्य जगहों पर लगातार जारी रहा, वह नकारात्मक साबित हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर ट्रंप को आमंत्रित करना और नवाज शरीफ से करीबी बढ़ाने के बाद हासिल नाकामी दोनों बताते हैं कि यह सब बिना तैयारी के किया गया।

4- अनुमान की कीमत: राजनीति, कूटनीति, युद्ध, खेल और जुआ, ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपकी आगामी चाल का अंदाजा नहीं लगना चाहिए। मोदी इस मोर्चे पर नाकाम रहे। विदेशी नेता उनकी शैली से वाकिफ हैं। उन्हें पता है वे प्रचार, तस्वीरों और तारीफ में रुचि रखते हैं। ये नेता जानते हैं कि मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए मोदी को इनकी जरूरत है। चीनी अब तक यह समझ चुके हैं कि मोदी चुनाव के पहले सीमा पर कोई घुसपैठ पसंद नहीं करेंगे। वे यह भी जान चुके हैं कि मोदी पाकिस्तान के साथ छोटी झड़प पसंद करेंगे ताकि तुरंत अपनी जीत की घोषणा कर सकें। चीन के साथ यह असंभव है। चीन ने अंदाजा लगा लिया है कि मोदी कब क्या प्रतिक्रिया देंगे।

पाकिस्तान ने भी कुछ चीजें समझ ली होंगी। उन्हें पता है कि मोदी अब बड़े आतंकी हमलों पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। अब पाकिस्तान मनचाहा संकट उत्पन्न कर सकता है। बड़े नेता खुद को मोहरा नहीं बनने देता।

5- विदेश नीति और घरेलू नीतियों को मिलाना: मोदी ने अक्सर अपनी विदेश नीति की पहल और शिखर बैठकों का इस्तेमाल घरेलू छवि निर्माण के लिए किया है। सबसे पहले चीन ने इसका फायदा उठाया। उसे पता था कि भारत चुनावी मौसम में घुसपैठ नहीं चाहेगा और उन्होंने इस बारे में अपनी शर्तों पर आश्वस्त किया। व्यापार में चीन का दबदबा बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान को लेकर उनका नजरिया कड़ा है और भारत मसूद अजहर के मामले में केवल प्रतिरोध कर पाया वह भी बिना नाम लिए। वुहान के बाद से भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता की मांग नहीं उठाई। अब अगर भारत मसूद अजहर पर प्रतिबंध चाहता है तो इससे दो बातें होती हैं: एक तो भारत चीन के समक्ष अपनी द्विपक्षीय हैसियत कमजोर करता है और दूसरा वह उसे यह अवसर देता है कि वह भारत के साथ अपनी नीति को पाकिस्तान से जोड़ सके। यानी भारत-चीन और पाकिस्तान का एक त्रिकोण, यही तो चीन चाहता था।

हमने मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल का बहीखाता पेश नहीं किया है। हमने केवल वे बातें दर्ज की हैं जो हमारी दृष्टि में उसकी सबसे बड़ी गलतियां हैं।

जांच में फर्जी तरीका अपनाने वाले अधिकारियों पर हो सख्ती

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

यह असली 'न्यू इंडिया' का एक अनूठा रूप है। न्यायपालिका की सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जा चुके छह घुमंतू कबायलियों को जेल से रिहा करने का असाधारण निर्णय सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पेश साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद इन अभियुक्तों को छोड़ने का निर्णय देकर उन्हें मौत के चंगुल में जाने से बचा लिया। उसने जेल में 16 साल तक कैद रहे हरेक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। इस मामले में गलत जांच करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक जांच का भी आदेश जारी किया गया है।

यह मामला न केवल हमारी आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में अंतर्निहित मुद्दों को उजागर करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था मृत्युदंड की सजा को लेकर किस कदर कमजोर है। यह मामला दीवानी प्रक्रिया को लेकर भी काफी कीमती सबक सिखाता है। आखिर दीवानी मामलों के भी फैसले किसी व्यक्ति का करियर तबाह कर देने या सामाजिक कलंक के बगैर जीवन व्यतीत करने की उसकी क्षमता को उसी तरह प्रभावित करते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की समीक्षा में अविश्वसनीय रूप से तर्कसंगत खामियां पाई हैं। इन खामियों के बारे में तीन अदालतें भी नहीं पता कर पाई थीं जिनमें खुद उच्चतम न्यायालय का पुराना पीठ भी शामिल है। जून 2003 में पांच लोगों की हत्या और एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में इन छह लोगों को दोषी ठहराया गया था। तीन वर्षों में नासिक सत्र अदालत ने इन लोगों को मौत की सजा सुनाई। बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में इनमें से तीन लोगों की मौत की सजा को कम कर दिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इन सभी लोगों की मौत की सजा बहाल कर दी थी।

यह ऐसा मामला साबित हुआ है जिसमें जांच एजेंसियों ने आरोपियों को फंसाने की कोशिश की है। उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले का अहम पहलू यह है कि अपराध के दौरान जिंदा बच गए एक शख्स ने घटना के तत्काल बाद पुलिस की तरफ से दिखाई गई तस्वीरों से चार एकदम अलग लोगों की शिनाख्त की थी। लेकिन काफी समय बाद इन छह कबायलियों की शिनाख्त कर ली गई और उन्हें ही मामले में आरोपी बना दिया गया। जांच के दौरान मिले कई अहम सुरागों की पड़ताल भी नहीं की गई। इस पहलू को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जांच में शामिल रहे अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को भी कहा है।

यह मामला देश में हर तरह की गतिविधि में शामिल नियामकीय संस्थाओं के लिए भी कई सबक समाहित किए हुए है। अपने लक्ष्य को हासिल करने और काम पूरा करने के दबाव के बीच इन नियामक एजेंसियों के अधिकारियों के लिए गलत प्रोत्साहन रहता है कि किसी को भी धोखाधड़ी या भेदिया कारोबार के गंभीर मामलों में आरोपी बना दिया जाए। इसके साथ अगर लापरवाही भी शामिल हो जाए तो ऐसे आरोप किसी भी व्यक्ति का करियर खत्म कर सकते हैं और उसके पूरे परिवार को बरबाद कर सकते हैं। यह दीवानी मामलों में मौत की सजा के ही बराबर है।

'नो वन किल्ड जेसिका' जैसी फिल्मों में समाज की इसी रक्त-पिपासु धारणा को संबल दिया जाता है, बनिस्बत कि इंसाफ दिलाने में सटीक तथ्य-अन्वेषण की जरूरत पर बल दिया जाए। इसी से 'सामूहिक चेतना' जैसी अब न्यायिक रूप से भी स्वीकृत अवधारणा का जन्म होता है जिनका ध्यान रखने की अपेक्षा न्यायाधीशों से भी की जाती है। समाज की सहज एवं चिरंतन सोच यही रही है कि वर्दी पहनने वाले लोग कभी भी जालसाजी नहीं करते हैं लेकिन आरोपियों की जिंदगी तबाह करने पर खमियाजा भुगतने का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने पर ऐसी धारणाओं की कोई अहमियत नहीं होती है।

दीवानी नियामकीय प्रक्रियाओं में केवल गलती होने के संदेह के ही आधार पर लोगों की जिंदगी को गहरे तक प्रभावित किया जा सकता है और उसके लिए किसी तरह की सुनवाई भी जरूरी नहीं होती है। इस तरह की अदालती प्रक्रिया में फैसला आने के बाद केवल नियंत्रण एवं संतुलन का ही प्रावधान होना समस्या को और गंभीर बना देता है। जबकि नियामकीय संस्थाएं इन मामलों में खुद ही अभियोजन और न्यायाधीश दोनों होती हैं।

जहां तक इस मामले का सवाल है तो निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय के पुराने पीठ तक अभियोजन पक्ष की तरफ से रखे गए तथ्यों से इत्तफाक रखते आए थे। इससे पता चलता है कि न्यायिक निगरानी किस हद तक असरहीन हो सकती है। टीवी चैनलों के प्राइम टाइम में होने वाली चर्चाओं में लोकप्रियता बटोरने के लिए जनभावनाओं को उकसाया जाता है और बुनियादी इंसानी कमियां ऐसी निगरानी को और कमजोर कर देती है।

इस मूलभूत समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि जांच करने वाले अधिकारियों को किसी मामले के सही निपटारे पर प्रोत्साहन देने के साथ ही फर्जी तरीके से केस हल करने पर हतोत्साहित भी किया जाए। इसी के साथ नियंत्रण एवं संतुलन साधने की भूमिका का निर्वाह नहीं करने पर भी उन्हें हतोत्साहित किया जाए। जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान सूत्रों के हवाले से मीडिया में आने वाली सुर्खियां अपने-आप में आरोपी के लिए गंभीर दंड से कम नहीं होती हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दूसरे पक्ष में होने भर से संदिग्धों को यह सजा मिलने लगती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने पीठ की गलती को भी स्वीकार कर एक नजीर पेश की है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

दिलचस्प घटनाक्रम

अमर सिंह की वापसी हो रही है। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुरादाबाद से और समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकीं जयाप्रदा को दोबारा रामपुर से ही चुनाव मैदान में उतार सकती है। जयाप्रदा को सन 2015 में सपा से निकाल दिया गया था और उन्होंने घोषणा की थी कि वह भाजपा में जा सकती हैं। परंतु अब तक उन्हें भाजपा की ओर से कोई न्योता नहीं मिला था। परंतु गत वर्ष जुलाई में रामपुर में आम लोगों को ईद की मुबारकबाद देते ऐसे पोस्टर नजर आए थे जिन पर जयाप्रदा की तस्वीर बनी थी। इस बीच उनके शत्रु बन चुके आजम खान ने घोषणा की है कि वह शायद अब चुनाव न लड़ें। भाजपा ने 2014 में नेपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था और वह जीते भी थे लेकिन इस बार शायद उनको टिकट न मिले। यह सीट इस बार जयाप्रदा को मिल सकती है। भाजपा इस बारे में इसलिए विचार कर रही है क्योंकि जयाप्रदा और आजम खान की दुश्मनी जगजाहिर है। सपा छोड़ते वक्त जयाप्रदा ने कहा था कि पार्टी के पास यह तमीज ही नहीं है कि औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कांग्रेस ने मुरादाबाद से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। वहां से सर्वेश कुमार सिंह भाजपा के मौजूदा सांसद हैं। वह मोदी लहर में भी केवल 80,000 वोट से जीत पाने में सफल रहे थे। अभी यह तय नहीं है कि अमर सिंह को वहां से टिकट मिल ही जाएगा क्योंकि वह अब तक पार्टी के सदस्य भी नहीं है। यह सीट भाजपा के लिए चुनौती बन गई है। वहां सपा काफी मजबूत है। पांच में से दो विधानसभाओं से सपा के विधायक हैं। अगर अमर सिंह को टिकट मिलता है तो वहां का चुनाव दिलचस्प होगा।

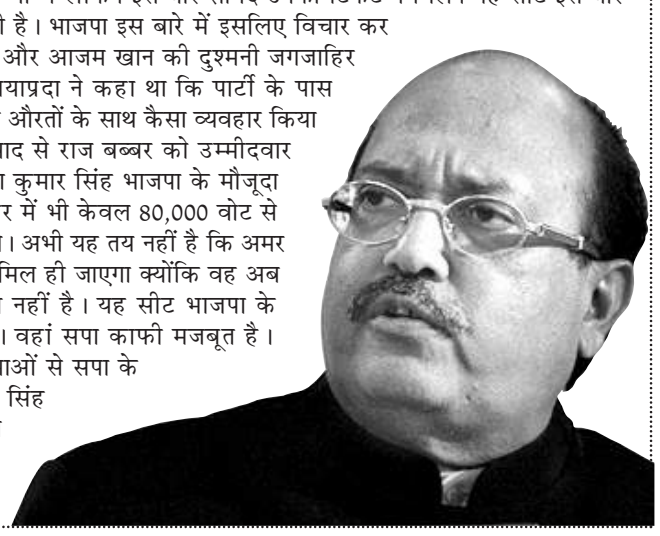

आपका पक्ष

आतंकवाद पर चीन का रुख

चीन ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो का प्रयोग कर चौथी बार आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया। भारत को अपनी रणनीति और कूटनीति को फिर से धार देने की जरूरत है जिससे भारत चीन को मात दे सके। चीन को मात देने के लिए भारत को आर्थिक तथा रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होना होगा। चीन पूरी दुनिया में व्यापार के दम पर धौंस दिखाता है। इस कारण उसका आर्थिक बहिष्कार करना ही होगा और यह चीन के लिए कठोर कदम होगा। वर्तमान में भारत दुनिया का छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत को और आगे जाना होगा। रक्षा बजट भले ही इतिहास में पहली बार तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर गया हो पर चीन को चुनौती देने के लिए काफी नहीं है। रक्षा बजट और बढ़ाने के साथ ही अगर हम जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्र को देते हैं तो यह एक मजबूत कदम होगा। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का प्रस्ताव लाना भारत की कूटनीतिक जीत है लेकिन चीन के अड़ियल रवैये से स्पष्ट हो चुका है कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद पर कौन साथ है और कौन नहीं? चीन का कहना है कि उसे जांच के लिए और समय चाहिए। अब कौन

पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए

सी जांच की आवश्यकता है? जब मानवता के दुश्मन हमले की खुलेआम जिम्मेदारी लेते हों। चीन वही गलती कर रहा है जो वर्षों पहले अमेरिका ने आतंकवाद को पोषण देकर किया और 9/11 जैसा आतंकी हमला हो गया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को मिलकर दूसरा प्रभावी कदम उठाने पर विचार करना होगा तथा चीन जैसे देश जो वीटो का गैर जिम्मेदाराना तरीके से पिछले 10 साल में चार बार किसी आतंकी को बचाने का प्रयोग किया हो उनकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जिस प्रकार से पूरे विश्व ने आतंकवाद पर एकजुटता दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार इस मुद्दे पर भी पूरे विश्व को एक मंच पर आना होगा, क्योंकि आतंकवाद अब भारत-पाकिस्तान तक सीमित ना रह कर पूरे विश्व में फैल चुका है। ऐसे देश जो आतंकवाद के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पोषक हैं उनका वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार होना आवश्यक है।

देवानंद राय, नई दिल्ली

भारत के 15 शहर विश्व में प्रदूषित

दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 15 शहर भारत के हैं। गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तथा भिवाड़ी शीर्ष छह प्रदूषित शहरों में शामिल है। यह खुलासा 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर पिछले साल विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र के रूप में उभरा है। राजधानी दिल्ली 11वें नंबर पर है। प्रदूषण विश्व की एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। किसी भी देश के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है। भारत में कस्बों तथा गांवों भी प्रदूषण की चपेट में आने लगे हैं। बेतहाशा बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या में इजाफा, छोटे कल-कारखाने, पेड़ों की कटाई आदि कई कारक हैं जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए जनअभियान चलाने की जरूरत है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।